

# सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-32 अंक-12

22 जून से 6 जुलाई, 2017

मुख्य संपादक : कॉमरेड प्रभास घोष

कुल पृष्ठ 8

मूल्य : 2 रुपये

## साम्प्रदायिकता, जात-पात, वर्णविद्वेष, वंशमूलीय नफरत को भड़का रहा है बेरोजगारी की समस्या के समाधान में नाकाम पूंजीवादी शासक वर्ग

70वें पार्टी स्थापना दिवस पर कोलकाता की जनसभा में  
कॉमरेड प्रभास घोष का भाषण

(कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में 70वें पार्टी स्थापना दिवस पर 24 अप्रैल 2017 को आयोजित जनसभा में एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष द्वारा बंगाली भाषा में दिए गये भाषण का अंग्रेजी अनुवाद पार्टी के अंग्रेजी मुखपत्र प्रोलिटेरियन एरा के 1 जून, 2017 के अंक में छपा था। यहां उसी को हिन्दी में रूपान्तरित करके प्रकाशित किया जा रहा है। अनुवाद या अभिव्यक्ति में रह गई किसी भी त्रुटि/खामी के लिए सर्वहारा दृष्टिकोण का सम्पादक मण्डल जिम्मेदार है।)

कॉमरेड अध्यक्ष जी, कॉमरेड-साथियो,

हर वर्ष हम पार्टी स्थापना दिवस 24 अप्रैल को पूरी गरिमा के साथ मनाते हैं। इस दिन हम इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी चिंतनकार, हमारे शिक्षक और एसयूसीआई(सी) के संस्थापक महासचिव कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होकर मौजूदा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने नये कार्यभारों का निर्धारण करते हैं।

हमारे देश के साथ-साथ पूरी दुनियां आज गंभीर और खतरनाक परिस्थिति से रूबरू है। पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी-पूंजीवादी अंधराष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता, नस्लवाद, वर्णविद्वेष और साम्प्रदायिकता को भड़का रहे हैं। लेकिन यह कोई आकस्मिक या अलग-थलग परिघटना नहीं है।

ट्रंप और मोदी, विचित्र समानताएं

विश्व पूंजीवाद आज गहन संकट में धंसा हुआ है। समाजवाद को लगे धक्के के बाद, आज भी दुनिया पर साम्राज्यवाद-पूंजीवाद के एकछत्र आधिपत्य के बावजूद प्रत्येक देश में पूंजीवाद गहन बाजार संकट से ग्रसित है। इसका मतलब है कि लोगों की खरीद शक्ति निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। साम्राज्यवादी-पूंजीवादी हल्कों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 300 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी मात्र 161 रुपये है। 1% सबसे अमीरों की सम्पदा बाकी 99% लोगों के बराबर है। मात्र 8 अति धनाढ्यों की सम्पदा दुनिया की आधी आबादी की सम्पदा के बराबर है। यह 99% आबादी पूंजीवादी बाजार में खरीदार है। यह है मौजूदा नजारा। एक समय 'सरक्षणवाद' की अवधारणा को बढ़ते बाजार संकट से



कोलकाता : सभा को सम्बोधित करते हुए कॉ. प्रभास घोष

निजात पाने के लिए पूंजीवाद-साम्राज्यवाद द्वारा ही लाया गया था। इसके मायने है कि सभी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देश अपने-अपने घरेलू बाजारों को विदेशी पूंजी के हमलों से बचायेंगे और बाहर के बाजार को हड़पेंगे। बाजारों के इस हड़पने की वजह से ही दो विश्व युद्ध हुए थे। बाद में शुरू हुए 'व्यापार युद्ध' और 'आर्थिक युद्ध'। 1990 के दशक में विश्व पूंजीवाद ने 'भूमण्डलीकरण' की स्कीम को लागू किया। 'सरक्षणवाद' की पहले की प्रस्थापना के विपरीत इस स्कीम ने मुक्त व्यापार के लिए तमाम बाजारों को खोलने का आह्वान (शेष पृष्ठ 2 पर)

मंदसौर (म.प्र.) में पुलिस फायरिंग कर किसानों को  
मौत के घाट उतारे जाने की एसयूसीआई(सी) ने की निन्दा

जायज मांगों को पूरा करवाने के लिए सही क्रान्तिकारी नेतृत्व में  
जोरदार आन्दोलन खड़ा करने का पीड़ित किसानों से आह्वान

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 8 जून, 2017 को जारी एक बयान में कहा : मध्यप्रदेश के मंदसौर में आन्दोलनकारी किसानों पर गत 5 जून को बीजेपी-नीत मध्यप्रदेश सरकार की पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से पांच किसानों को मौत के घाट उतारे जाने की हमें कड़ी निन्दा करते हैं। यह उसी प्रदेश की घटना है जिसे भाजपा नेता कृषि में प्रगति के एक मॉडल के रूप में पेश करते हैं। किसान न्यायोचित रूप से मांग कर रहे थे कि सरकार उनके कर्ज माफ करे और उनकी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे। म.प्र. में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी प्रान्त महाराष्ट्र, दूर दराज के प्रान्त तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पंजाब आदि प्रान्तों के दुखियारे किसान असंतोष से खौल रहे हैं और विभिन्न रूपों में आन्दोलन कर रहे हैं, कर्ज माफी और फसलों के लाभकारी दाम मांग रहे हैं। सूखा-पीड़ित महाराष्ट्र के किसानों ने दो दिन का बंद किया और तमिलनाडु के किसानों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर 40 दिन धरना दिया। किसानों को झांसा देने के लिए विभिन्न राज्य सरकारें चुनिन्दा फसलों के लिए कड़ी

(शेष पृष्ठ 8 पर)

देशव्यापी मांग दिवस पर एसयूसीआई(सी) ने की सभाएं, रैलियां  
मंदसौर (म.प्र.) में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को दी श्रद्धांजलि

किसान आन्दोलन के समर्थन में एस.यूसी.आई.(सी) की केन्द्रीय कमिटी के आह्वान पर 14 जून 2017 को देशभर में मांग दिवस मनाया गया। मंदसौर (म.प्र.) में पुलिस की गोली से मरे किसानों की याद में शहीद वेदी बना कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जगह-जगह नुक्कड़ सभाएं, धरने-प्रदर्शन किये गए और किसानों की मांगों के ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में मांग की गई कि किसानों के सभी लोन माफ कर दिए जाएं, कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य की गारंटी दी जाए, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और परिवार के कम से कम एक सदस्य को स्थायी नौकरी प्रदान की जाए, इस जघन्य कांड में संलिप्त दोषी पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं को उदाहरणमूलक सजा दी जाए।



दिल्ली : जंतर मंतर पर धरना देते हुए एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) कार्यकर्ता

दिल्ली

एस.यूसी.आई.(सी)की दिल्ली राज्य सांगठनिक कमिटी द्वारा किसानों की मांगों के समर्थन में जंतर-मंतर पर धरना दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा पार्टी के जनसंगठनों जैसे एम.एस.एस., डी.एस.ओ., डी.वाई.ओ. तथा ए.आई.यू.टी.यूसी. के कार्यकर्ताओं ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित करते हुए मंदसौर (म.प्र.) में पुलिस फायरिंग में मारे गए आन्दोलनकारी किसानों को श्रद्धांजलि दी। धरना सभा को एस.यूसी.आई.(सी) की दिल्ली राज्य सांगठनिक कमिटी के सदस्यों तथा जनसंगठनों के नेताओं ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने मंदसौर में 5 जून 2017 को आंदोलनकारी किसानों को पुलिस द्वारा गोली से मार दिए जाने तथा कड़ियों को घायल कर देने की घटना की कड़ी निन्दा की तथा किसानों से आह्वान किया कि वे सही क्रान्तिकारी नेतृत्व के दिशा निर्देशन में जोरदार आन्दोलन को खड़ा करें तथा अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए एकजुट हो जाएं।

हरियाणा

रोहतक : आन्दोलनकारी  
किसानों पर लाठी-गोली के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

## कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 1 का शेष)

किया। स्कीम को लागू करने के नाम पर शक्तिशाली साम्राज्यवादी-पूँजीवादी देशों ने कम विकसित या विकासशील देशों के बाजारों पर कब्जा जमाने का अभियान छेड़ दिया, जिन्होंने एक समय समाजवादी खेमों से मदद लेते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने का प्रयास किया था। अब भूमण्डलीकरण का बुलबुला फूट चुका है। विश्व पूँजीवाद-साम्राज्यवाद गहन मंदी की गिरफ्त में है। अमेरिका में भी करोड़ों बेरोजगार हैं, लाखों मजदूरों की छंटनी हो गई है। अमेरिका में हुए पिछले राष्ट्रपति चुनाव पर एक नजर डालें। उस चुनाव को केन्द्र करके उपराष्ट्रीयताओं के प्रति नफरत, उग्र राष्ट्रवाद और नस्लवाद के सड़े-गले विचारों की भरमार थी। “अमेरिका है अमेरिकियों के लिए”, अमेरिका है श्वेत अमेरिकियों के लिए। प्रवासियों, लैटिन अमेरिकियों और काले अमेरिकियों को बाहर खदेड़ो”-इस तरह के नारे उठाये गये थे। काले अमेरिकी जो अमेरिकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं उनके खिलाफ नस्लीय जहर उगला गया। सत्तासीन होने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि कुछ चुनिंदा मुस्लिम देशों के नागरिकों को वह अमेरिका में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगा। भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं उनके लिए एच 1-बी वीजा जारी करने पर कठोर प्रतिबंध थोप दिये गये। इन सबका क्या कारण है? कारण है कि अमेरिकी युवाओं के लिए रोजगारों की भारी कमी है। उन्हें रोजगार देने की जरूरत है। इसीलिए दूसरों को खदेड़ने का कदम उठाया जा रहा है। मात्र कुछ वर्ष पहले ही पूरा अमेरिका “वॉल स्ट्रीट दखल करो आंदोलन” से हिल उठा था। अमेरिकी युवाओं ने उस आंदोलन को सात महीने के लम्बे असें तक जारी रखा था। उन्होंने नारा बुलंद किया था-“पूँजीवाद मुर्दाबाद”, “भूमण्डलीकरण मुर्दाबाद”, “हम 99% हैं और वो 1% हैं”। ‘वॉल स्ट्रीट दखल करो’ आंदोलन इतना जोशीला और जोरदार था। इसका कोई नेता नहीं था दिशा निर्देशन के लिए कोई विचारधारा नहीं थी। भूखे क्षुब्ध अमेरिकी स्वतःस्फूर्त आंदोलन में फूट पड़े थे। इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे तमाम साम्राज्यवादी देशों में इस तरह के प्रतिवाद आंदोलन समय-समय पर उभर रहे हैं। ऐसे उभरते हुए प्रतिवाद आंदोलनों के रूबरू पूँजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति की संभावना से भयाक्रांत साम्राज्यवादी-पूँजीवादी शासक धार्मिक और नस्लवादी नफरत की आग भड़का रहे हैं। जन-संघर्षों से भयभीत विश्व पूँजीवादियों-साम्राज्यवादियों की यह एक गहरी साजिश है।

### चपरासी के 368 पदों के लिए

#### 23 लाख आवेदन

भारत में भी स्थिति कोई भिन्न नहीं है। चार साल पहले भारत के राष्ट्रपति ने खुद कहा था कि 121 करोड़ की आबादी में से 66 करोड़ लोग यानी आधी आबादी बेरोजगार है। एक बहुत ही कम आंकलन के आधार पर भी यह संख्या अब लगभग 70 से 75 करोड़ होगी। यदि अर्ध-बेरोजगारों की संख्या इसमें जोड़ दी जाये तो आंकड़ा 80 से 90 करोड़ तक पहुंच जायेगा। पिछले वर्ष खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में चपरासी के मात्र 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदकों में सभी स्त्रीयों से डॉक्ट्रेट, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट शामिल थे। इसी प्रकार ‘ग्रुप डी’ के 6000 पदों के लिए पश्चिम बंगाल में 25 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ‘आठवीं पास’ थी। भारी संख्या में डॉक्ट्रेटों, इंजीनियरों, पोस्ट ग्रेजुएटों और ग्रेजुएटों ने आवेदन किया था। यह है शिक्षित बेरोजगारों की हालत। यदि अशिक्षित बेरोजगारों और छंटनी किये गये मजदूरों को भी इसमें जोड़ दिया जाये, तो उस संख्या का अंदाजा लगाइये। हजारों उद्योगों के शटर बंद पड़े हैं। लाखों मजदूरों को काम से बाहर कर दिया गया है। खेती का आलम भी वैसा ही खौफनाक है। बार-बार पड़ने

वाले सूखे और बाढ़ से किसान तबाह हैं। पिछले कुछ सालों में 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये है हमारे देश में विकास का नजारा।

### बच्चों और महिलाओं की तस्करि

हमारे देश में महिलाएं और बच्चे वस्तुतः बाजार की वस्तु हैं। भुखमरी के शिकार मां-बाप गरीब परिवार मात्र चंद सिक्कों के लिए आंसू भरी आंखों से अपने बच्चों को बेच रहे हैं। ये बच्चे कहाँ जाते हैं? उन्हें बंधुओं मजदूर बना कर रखा जाता है। मालिक उनसे लम्बी अवधि तक चारदीवारी में बंद जर्जर गंदी दुकानों या फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं। इन बाल श्रमिकों के लिए काम के घंटे निर्धारित नहीं हैं, न ही इन्हें कोई वेतन दिया जाता है। उन्हें सिर्फ खाना मिलता है, वह भी पूरा नहीं। ऐसे बंधुआ मजदूर हमारे देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में बहुतायत में हैं। बाल श्रमिकों सहित भारत में 1.2 करोड़ बंधुआ मजदूर हैं। इसी तरह नारी शरीर भी बाजार में खरीद-फरोख्त की चीज है। इसी खरीद-फरोख्त की वस्तु को बाजार में बेचने के विभिन्न तरीके हैं। कभी-कभी औरतों को शादी के नाम पर भी धोखा दिया जाता है। अन्य मामलों में गरीबी के शिकार अभिभावक अपनी लड़कियों की शादी 10 से 15 हजार रुपये के एवज में कर देते हैं। फिर ऐसी लड़कियों को वेश्यालयों में बेच दिया जाता है। यह कृत्स्न व्यापार भारत के लगभग हर राज्य में चल रहा है। पश्चिम बंगाल भी देह व्यापार के लिए फलता-फूलता बाजार है। इस तरह के ‘विकास’ को यह राज्य भाग रहा है।

### प्रदुषित होता सामाजिक वातावरण

अतः पूरे देश को एक असहनीय स्थिति में धकेल दिया गया है। एक तरफ करोड़ों शिक्षित और अशिक्षित नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लाखों छंटनी और ले-ऑफ किये गये मजदूर काम की कमी के लिए अपने भाग्य को कोस रहे हैं जबकि दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं, रसोई गैस और दवाइयों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, टेक्स, रेलवे किराये भाड़े में बढ़ोतरी हो रही है। शिक्षा का खर्च बढ़ता जा रहा है। यह असहनीय स्थिति लोगों के अंदर विश्कोभ पैदा कर रही है और अक्सर ऐसा विश्कोभ यहां वहां स्वतःस्फूर्त आंदोलनों में फूट पड़ता है। कहीं ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन एक संगठित संघर्ष का रूप न ले लें, इसलिए एक सुनियोजित योजना के तहत सुसंगठित प्रयास किये जा रहे हैं। धार्मिक नफरत और साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने के लिए अलौकिक, मनगढ़ंत, गैर वैज्ञानिक और गैर-ऐतिहासिक विचारों और नजरिये को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके जरिये देश को फासीवादी अंधकार में धकेला जा रहा है। इसके बिना पूँजीवाद के लिए बचे रहने का और कोई जरिया नहीं है। दकियानूसी प्रतिक्रियावादी दमनकारी पूँजीवाद की अंतिम शरण स्थली यही है। मैं अन्य बात कहना चाहता हूं। पूँजीवाद अपनी मृत्यु शैया पर है, यह सडती हुई लाश है जो प्रदूषण फैला रही है। यह आर्थिक-राजनैतिक-नैतिक सभी पहलुओं से पतित और सड़ी-गली व्यवस्था हो गयी है। इसलिए बुर्जुआ राजनीतिज्ञ जो सड़े-गले मरणासन्न पूँजीवाद के सेवादार के रूप में राजसत्ता और सरकार को चला रहे हैं, वे भी पतित, भ्रष्ट और ढोंगी हो गये हैं। आप पायेंगे कि हमारे देश की तमाम शासक पार्टियों में इस तरह के पतित चरित्र भरे पड़े हैं।

### एक चीज नहीं है

#### धर्म में विश्वास व धार्मिक नफरत

एक बिन्दु का उल्लेख करने की यहां जरूरत है। धर्म में विश्वास और धार्मिक नफरत एक नहीं है। हम मार्क्सवादी हैं, हम नास्तिक हैं। हालांकि ईमानदार धार्मिक प्रचारकों के साथ हमारे दार्शनिक मतभेद हैं फिर भी उनके साथ हमारा इतना विरोध नहीं है बल्कि उनमें से बहुत से जो ईमानदारी के साथ धार्मिक गतिविधियां करते हैं, वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष में हमारे सहयोद्धा होंगे। हम उनके सख्त खिलाफ हैं जो धर्म का धंधा करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं और निहित

राजनैतिक स्वार्थ साधने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निहित स्वार्थ के हलकों द्वारा निरंतर दुष्प्रचार चलाया जा रहा है कि मार्क्सवादी लोग धार्मिक प्रचारकों का अनादर करते हैं। यह सही नहीं है। इसके विपरीत उभारशील बुर्जुआ वर्ग जब सामंती राजशाही के खिलाफ लड़ रहा था, तब स्पिनोजा, होब्स, लॉक, कांट और फ्यूरबाख जैसे बुर्जुआ मानवतावादियों, यात्रिक वस्तुवादियों और धर्मनिरपेक्ष मानवतावादियों ने धर्म में विश्वास के विचार पर हल्ला बोला था और माना था कि धर्म इतिहास का एक भटकाव है। उनके अनुसार धर्म इतिहास के विचलन या भटकाव की तरह है। इसलिए उन्होंने सोचा कि धर्म को तिरस्कृत करना चाहिये। प्रथम बार मार्क्स ने ही यह दिखाया कि मानवजाति के इतिहास में धर्म की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गहरी श्रद्धा के साथ मार्क्स ने कहा कि “धार्मिक व्यथा साथ ही साथ असल व्यथा की भी अभिव्यक्ति है और असल व्यथा के खिलाफ प्रतिवाद भी है। धर्म उत्पीड़ित जनों की आह है, हृदयहीन दुनिया का हृदय और प्राणहीन परिस्थितियों का प्राण है।” (अधिकार संबंधी हेगलीय दर्शन की आलोचना) मार्क्स ने दिखाया कि धार्मिक विचारों का जन्म उत्पीड़ित गुलामों के आंसुओं और आहों से हुआ है। धर्म समाज के अंदर हृदय और चेतना लेकर आया जो अब तक इससे महरूम था। इस प्रकार हम मार्क्सवादियों ने इतिहास में धर्म की उचित भूमिका और स्थान की श्रद्धापूर्वक स्वीकार्यता के जरिये धर्म के पनपने और विकसित होने का वस्तुपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। दास-दास प्रभु सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इस्लाम और ईसाई धर्म की भूमिका का उल्लेख करते हुये कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था कि “आपको यह याद रखना चाहिए कि सामाजिक विकास के एक विशेष स्तर पर यह धर्म ही था जिसने नीति-नैतिकता की अवधारणा, मूल्यबोधों, सही-गलत की अवधारणा, दूसरों की सेवा करने और किसी से भी नफरत न करने की भावना को आगे बढ़ाया था। इसके परिणाम स्वरूप अनुशासन की भावना पनपी थी जिसने समाज में सुदृढ़ीकरण और एकजुटता कायम करने में मदद की थी। इस नजरिये से भी धर्म ने सामाजिक प्रगति में एक भूमिका निभाई थी।” (मार्क्सवाद और द्वंद्वत्मक भौतिकवाद के कुछ पहलू) इस परिप्रेक्ष्य में धर्म ने समाज में एक प्रगतिशील भूमिका निभाई थी। यह भी सही है कि सामंती राजशाही व्यवस्था जो दास-दासप्रभु व्यवस्था को उखाड़ फेंक कर आई थी धर्म पर आधारित थी।

### भारत के सनातन नहीं हैं धार्मिक संस्कार

इस बारे में और भी चौकस रहने की जरूरत है। धार्मिक विचारों के बारे में यह अवधारणा गलत है कि ये तो मानव समाज के शुरूआत से ही हैं। ऐसी कोई नजीर इतिहास में नहीं है। आज भी, अफ्रीका या जरोआ के घने जंगलों में रह रहे मूल निवासी और अंडमान के द्वीपों में निवास करने वाले अंडमानी कबीले भगवान के किसी भी विचार के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। वे किसी भगवान की पूजा नहीं करते हैं। लेकिन वे सभी इन्सान हैं। आदिम समाज में स्थाई सम्पत्ति नहीं थी, सम्पत्ति पर व्यक्तिगत मालिकाना नहीं था। अमीर-गरीब का भेद नहीं था या शासक और शासित का विभाजन नहीं था। उस समय, कबीले के लोग जिंदा रहने के लिए सामूहिक तौर पर प्रकृति का मुकाबला किया करते थे, ‘मंत्रोच्चारण’ किया करते थे, प्राकृतिक ताकतों को शांत करने और वश में करने के लिए विभिन्न तरह के ‘मैजिक’ यानी जादू-टोनों का सहारा लिया करते थे। लेकिन वे किसी अति-प्राकृत या अलौकिक सत्ता के बारे में नहीं जानते थे, उनमें भगवान की कोई अवधारणा नहीं थी। उस समय उनका विचार वस्तुवादी था। विवेकानंद ने खुद बताया था कि, “ब्रह्माण्ड की सच्चाइयों के बारे में प्रथम खोज बाह्य प्रकृति में हुई थी, वस्तुगत जगत से जीवन की समस्याओं के समाधान ढूँढने का यह एक प्रयास था।” (अद्वैत वेदांत, एक

(शेष पृष्ठ 4 पर)

## सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक पास-फेल प्रणाली लागू करवाने के लिए ऑल इण्डिया डीएसओ ने हरियाणा में छेड़ा आन्दोलन

नई दिल्ली : ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी की दिल्ली राज्य इकाई ने पास-फेल पद्धति पुनः लागू करवाने की मांग को लेकर 8 जून को जन्तर-मन्तर पर धरना प्रदर्शन किया।

स्कूली शिक्षा को चौपट कर देने वाली विनाशकारी फेल न करने की (नो डिटेन्शन) नीति ने छात्रों, अध्यापकों और जनसाधारण सहित सभी को गहरी चिन्ता में डाल रखा है। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों व अभिभावकों ने इस पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। सभा में बोलते हुए शिक्षकों ने बताया कि सत्र के अंत में परीक्षा के आधार पर स्कूलों में छात्रों को अगली कक्षा में उत्तीर्ण करने के परम्परागत तरीकों को हटा कर अब जो बेरोकटोक पास करने की नीति को अपनाया जा गया है इसने छात्रों में अध्ययन की चाह और अध्यापकों में अध्यापन की इच्छा ही छीन ली है। अब पूरी शिक्षण प्रक्रिया एक तुच्छ, बेजान कवायद बन गई है। ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी, दिल्ली के अध्यक्ष प्रो. नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत यह नीति केन्द्र की कांग्रेस-नीत यू.पी.ए.-2 सरकार लाई थी जिसे भाजपा-नीत एन.डी.ए. सरकार ने तथा अन्य राज्य सरकारों ने लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जो पार्टियाँ सत्ता में नहीं थीं उनके द्वारा भी इस नीति का अनुमोदन किया गया। प्रो. शर्मा ने बताया कि ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी ने छात्रों और आम जनता के साथ मिलकर एक देशव्यापी जन आन्दोलन खड़ा करने का बीड़ा उठाया है और सरकार से यह पुरजोर मांग करती है कि इस विनाशकारी 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' को तुरन्त रद्द करे।

ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन कमेटी के दिल्ली राज्य सचिव श्री गिरवर सिंह ने बताया कि इस मुद्दे पर किस प्रकार संसदीय स्टैण्डिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में पास-फेल प्रणाली दोबारा शुरू करने के पक्ष में ही राय दी थी। परन्तु भाजपा-नीत एन.डी.ए. सरकार अब भी इस पर कोई निर्णय न लेकर टालमटोल कर रही है। वर्तमान में यह भ्रम भी फैल रहा है मानो फेल न करने की पद्धति वापस ले ली गई हो। परन्तु हकीकत में यह अब भी लागू ही है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।

सभा के अंत में एक डेलिगेशन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पास-फेल पद्धति पुनः चालू करने हेतु एक ज्ञापन दिया और मांग की कि मंत्रालय पास-फेल प्रणाली तुरन्त लागू करे और इस मुद्दे पर टालमटोल बंद करे। साथ ही साथ धड़ल्ले से हो रही फीस वृद्धि, निजीकरण-व्यापारीकरण शिक्षा के साम्प्रदायीकरण पर रोक लगाई जाए। सही मायने में वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शिक्षा देश में लागू करे।

धरने को छात्रा प्रतीक्षा, अभिभावक संध्या एवं प्रभाष, अध्यापकों में से साधना दीक्षित, निरन्जन देव, छात्र नेता प्रशांत कुमार एवं मो. आसिफ आदि ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम को संयुक्त रूप से भास्कर एवं गिरवर सिंह ने संचालित किया।

**रोहतक :** पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूलों में पास-फेल प्रणाली लागू करवाने, पांचवीं और आठवीं में बोर्ड परीक्षा लागू करवाने व 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम का निःशुल्क पुनर्मूल्यांकन करवाने, स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक भर्ती करवाने की मांगों को लेकर 7 जून को छात्र संगठन ऑल इण्डिया डीएसओ की ओर से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को उपायुक्त, रोहतक की



रोहतक: अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए डीएसओ का प्रतिनिधिमण्डल मार्फत ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश सचिव डॉ. हरीश कुमार सैनी ने किया।

छात्र नेता ने कहा कि पिछले कई सालों से हरियाणा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा का परिणाम घट कर 30 फीसदी तक जा चुका है। इतना ही नहीं रीचेकिंग के फार्म के नाम पर 1000 रुपये फीस वसूल कर छात्रों को लूटा जा रहा है। प्रदेश के गरीब छात्रों के प्रति घोर अन्याय हो रहा है। स्कूलों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं हैं, लैब, बिजली, पानी, भवन व शौचालय समेत आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। इसी कारण सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। सरकार छात्रों की संख्या घटने का बहाना बना कर चालाकी से क्लोजर और मर्जर की नीति के तहत स्कूलों को बंद कर रही है। असल में सरकारी नीतियाँ ही सरकारी स्कूलों की इस दयनीय हालत के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रदर्शन में विप्लव, सिकंदर, रवि अहलावत, स्फूर्ति सुहाग, पवन जसिया व नमन आदि शामिल रहे।

**भिवानी** स्कूलों में पास-फेल प्रणाली लागू करवाने व अन्य मांगों को लेकर 7 जून को शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार को उपायुक्त, भिवानी की मार्फत ज्ञापन सौंपा।

## मंदसोर (म.प्र.) में किसानों पर गोली चलाने की भाजपा सरकार की बर्बर कारवाई की कड़ी भर्त्सना

**रोहतक (हरियाणा) :** 7 जून 2017, ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष डॉ. सत्यवान व महासचिव डॉ. शंकर घोष ने आज जारी किए एक साझे बयान में कहा कि भाजपा की मध्यप्रदेश सरकार ने 6 किसानों की हत्या उस वक्त कर दी जब वे अपनी ज्वलन्त मांगों को बुलन्द करने के लिए एक विरोध रैली कर रहे थे। इसमें कई किसान घायल भी हुए हैं। भाजपा सरकार की इस बर्बर कारवाई की उन्होंने कड़ी भर्त्सना की। साथ ही उन्होंने मांग की कि मृतकों व घायलों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और उन पुलिस अफसरों व राजनैतिक नेताओं को उदाहरणमूलक सजा दी जाए जो इस बर्बर कारवाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं।

उन्होंने सभी मेहनतकशों व जनतान्त्रिक सोच के लोगों से इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करने और 8 जून

(नीचे) 14 जून को देशव्यापी विरोध दिवस पर अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के पास प्रदर्शन

ए.आई.डी.वाई.ओ. के जिला सचिव सन्दीप मेहरा और ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. के दीपक जांगड़ा ने कहा कि आज प्रदेश भर में हमारे संगठनों की तरफ से बेरोकटोक पास नीति का विरोध किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि संसदीय स्थाई कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि 53.3 फीसदी छात्र दूसरी कक्षा की पुस्तकें तक नहीं पढ़ सकते, 46.6 फीसदी छात्र दो अंकों की सामान्य जोड़-घटा भी नहीं कर सकते। सरकार का यह तर्क गलत साबित हो गया है कि 'पास-फेल प्रणाली' बीच में पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण है। 'नई शिक्षा नीति-2016' के मसौदे में सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि पहली कक्षा के 10 में से 4 छात्र आठवीं कक्षा तक पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन्होंने पास-फेल प्रणाली तुरंत लागू करने की मांग की।

ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमण्डल में सन्दीप मेहरा, दीपक जांगड़ा, विकास, आशीष, मनीषा, अल्का आदि शामिल रहे।

**गुड़गांव :** कक्षा पहली से आठवीं तक पास-फेल प्रणाली पुनः लागू करवाने आदि मांगों को लेकर 7 जून को आल इण्डिया डीवाईओ ने यहां धरना-प्रदर्शन किया और डीसी, गुड़गांव की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना-प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इण्डिया डीवाईओ के नेता डॉ. बलवान सिंह ने किया।

प्रदर्शन में सुनील कुमार, वजीर सिंह, महेन्द्र सिंह, राम कुमार आदि ने हिस्सा लिया।

**तावड़ :** आठवीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा लागू करने, पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षक भर्ती करने, हाल ही के 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम की निःशुल्क जांच करवाने की मांग पर 7 जून को ऑल इण्डिया डीएसओ की ओर से यहां प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त की मार्फत ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व डी.एस.ओ. के जिला सचिव मोहन सैनी ने किया।

प्रदर्शन में डीवाईओ के जिला सचिव महेश कुमार, किशन शर्मा व देवीलाल, बृजमोहन भी शामिल थे।

को पूरे देश में अखिल भारतीय विरोध दिवस आयोजित करने का आह्वान किया।



(ऊपर) 14 जून को सागर (म.प्र.) में सभा को सम्बोधित करते हुए एसयसीआई (सी) के नेता डॉ. रामावतार शर्मा



रेवाड़ी : पहली कक्षा से 8वीं तक पास-फेल प्रणाली लागू करने की मांग पर प्रदर्शन करते हुए ऑल इण्डिया डीएसओ कार्यकर्ता



## कॉ. प्रभास घोष का भाषण

(पृष्ठ 2 का शेष)

वैज्ञानिक धर्म) वे महान व्यक्ति थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि भगवान में आस्था शुरूआत से ही थी। प्राचीन भारत में बुद्ध हालांकि उनको भगवान बुद्ध के रूप में जाना जाता है जबकि उन्होंने भगवान में विश्वास नहीं किया। जैन धर्म के संस्थापक महावीर ने भी भगवान में विश्वास नहीं किया। इस देश में एक समय माना जाता था कि इस वस्तु जगत में हर चीज पंच भूतों या पांच मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बनी है। कुछ आकाश को छोड़कर सिर्फ चार तत्वों में यकीन करते थे। कणाद ऋषि ने कहा था कि हर चीज सुक्ष्मतम वस्तु कणों से मिलकर बनी है। गणित में एक महत्वपूर्ण अंक के रूप में 'जीरो' की खोज भी इसी देश में हुई थी। दर्शन (जो संस्कृत में फिलासफी का प्रयायवाची है जिसका मतलब है "जो मैं देखता हूँ वह सत्य है।" यह विचार भी इसी देश में उत्पन्न हुआ था। आज भी भारतीय भौतिकवादी दर्शन, चार्वाक मुनि और लोकायत (दुनिया से संबंधित), वस्तुवादियों का एक भारतीय दार्शनिक स्कूल जो 'परलोक' की कर्म, मोक्ष की अवधारणा की, पवित्र ग्रंथों, वेदों की अथोरिटी और आत्मा की अमरता की अवधारणा को नकारता है हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाता है।

इसलिए ये कहना गलत है कि भारत की धार्मिक परम्परा सनातन है। धार्मिक विचारों का उदय दासप्रभु व्यवस्था के दौरान हुआ। यह इस सादृश्य पर आधारित था कि चूकि दासों का प्रभु समाज को एक व्यवस्थित तरीके से चला रहा है, इसी तरह दुनिया का भी एक स्वामी होना चाहिए जो इसे व्यवस्थित तरीके से चला रहा है। जैसाकि दास प्रभु उसके द्वारा बनाये गये कुछ नियमों के आधार पर समाज को चलाता है, वैसे ही मनुष्य को लगा कि दुनिया का भी कोई स्वामी होगा जो प्रकृति को रेगुलेट कर रहा है ऋतु परिवर्तन को संचालित करने वाले, दिन-रात के चक्र को निर्धारित करने वाले, जीवन-मरण को नियमित करने वाले इत्यादि नियम बना रहा है। इस तरह से भगवान की अवधारणा का उदय हुआ और इसका अनुसरण करते हुए उत्पीड़ित दासों के आंसुओं के रूप में धर्म आया दासों की मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए।

### कौन असल हिन्दू है-विवेकानंद या आर.एस.एस-बीजेपी के नेतागण

इसके बाद, धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए शासन की राजतंत्रीय व्यवस्था आयी और मध्ययुगीन दमन-शोषण चलाया गया। हमारे देश में एक तबका दलील देता है कि कोई भगवान और धर्म का पालन नहीं करता है, तो उसकी नीति-नैतिकता व चरित्र ऊँचा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो उन्हें कहना पड़ेगा कि विद्यासागर, शरतचंद्र, शहीद-ए-आजम भगतसिंह, इनमें से किसी के अंदर न तो नैतिकता थी और न ही चरित्र था। फांसी का फंदा चूमने से पहले भगतसिंह ने 'मैं नास्तिक क्यों' शीर्षक से एक पुस्तिका लिखी थी। क्या वे ऊँचे नैतिक चरित्र के धनी नहीं थे? क्या आस्तिक रामकृष्ण और विवेकानंद धर्मनिरपेक्ष विद्यासागर के लिए गहरी श्रद्धा नहीं रखते थे? अतः इस प्रकार के विचार सही नहीं हैं।

मैं विवेकानंद के कुछ उद्धरण यहां प्रस्तुत करूंगा उनके लिए जो आज धार्मिक हिन्दुत्व का नारा उठा रहे हैं। सबसे पहले आर.एस.एस.-बीजेपी ने बाबरी मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्मारक को ध्वस्त कर दिया वहां राम मंदिर स्थापित करने का उन्माद भड़का कर। जिस तरह अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की ऐतिहासिक प्रतिमा को ध्वस्त करने के अपराधी तालिबान हैं, भारत में वैसे ही अपराध करने के दोषी आर.एस.एस.-बीजेपी भी हैं। हमने यह सवाल उठाया था कि चैतन्य, रामकृष्ण और विवेकानंद के समय में भी बाबरी मस्जिद थी। लेकिन, क्यों इन तीनों धार्मिक हस्तियों ने जिन्हें हिन्दू धर्म के अंतिम व्याख्याता माना जाता है, कभी राममंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का नारा

नहीं उठाया? क्या वे कायर थे या ऐसा करने में अक्षम थे? बल्कि सुनिये इस संबंध में विवेकानंद का क्या कहना है। उन्होंने कहा था, "रामायण का मामला लीजिए। बात ऐसी नहीं है कि इसे एक पवित्र विश्वसनीय महाकाव्य के रूप में स्वीकार कर लेने से ही किसी को राम के अस्तित्व पर विश्वास करना ही होगा। धर्म की जिस महिमा को रामायण और महाभारत ऊँचा उठाते हैं वह राम या कृष्ण के अस्तित्व या अस्तित्वहीनता पर निर्भरशील नहीं है...यह पड़ताल करने के लिए कि दार्शनिक सत्य कितना विश्वसनीय है इस बात की छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है कि इन महाकव्यों के पात्र वास्तव में ही अस्तित्वमान थे या वे मात्र काल्पनिक चरित्र हैं।" (वर्क्स एण्ड मैसेजिस, उद्धबोधन) अतः यह देखा जा सकता है कि विवेकानंद का मानना था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम या कृष्ण वास्तविक थे या कल्पित चरित्र थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि रामायण या महाभारत से कौन क्या सीखता है। इससे यह स्पष्ट है कि विवेकानंद खुद भी नहीं कहते हैं कि राम और कृष्ण जैसे कोई असल व्यक्ति भी थे या उनका जन्म स्थान क्या था। बल्कि उन्होंने आह्वान किया कि यदि कोई भक्त बनना चाहता है तो उसके लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था या नहीं, उसने ठीक-ठीक क्या किया था या ठीक-ठीक कब गीता का ज्ञान दिया था। ये थे विवेकानंद। क्या वे एक हिन्दू नहीं थे? क्या वे हिन्दू हैं जो राम मंदिर का भड़काऊ नारा उछाल रहे हैं? हम ये सवाल उठाना चाहते हैं।

विवेकानंद ने खुद कहा था, "ईसाइयो को बौद्ध बनने की जरूरत नहीं है न ही मुसलमानों को हिन्दू या बौद्ध या ईसाई बनने की जरूरत है। लेकिन इनमें से प्रत्येक का पोषण दूसरे धर्मों के सारतत्व को आत्मसात करने के जरिये होगा और अपनी अलग पहचान को बरकरार रखते हुए अपनी प्रकृति के अनुरूप विकसित होगा...। हम मानवजाति को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां कोई वेद, बाइबल या कुरान नहीं होगी बल्कि सभी कार्य वेद, बाइबल और कुरान के समन्वय के माध्यम से अंजाम दिये जायेंगे। (वर्क्स एण्ड मैसेजिस, उद्धबोधन, प्रथम संस्करण, प्रथम खण्ड) उन्होंने आगे कहा कि, "यदि मेरा एक पुत्र होता, तो ध्यान लगाने के, एक पैरा प्रार्थना का और मंत्रों का उच्चारण के सिवाय मैंने उसकी कोई धार्मिक सरपस्ती नहीं की होती। इसके बाद उम्र बढ़ने के साथ-साथ वह ईसा, बुद्ध या मोहम्मद, जिसको भी उसका जी चाहे स्वीकार कर सकता था...यह बहुत ही स्वाभाविक है कि पूर्ण स्वतंत्रता के साथ और बिना किसी द्वंद्व के एक ही साथ मेरा बेटा बौद्ध हो सकता है, मेरी पत्नी ईसाई और मैं मुसलमान हो सकता हूँ।" (वर्क्स एण्ड मैसेजिस, उद्धबोधन, तृतीय खण्ड)

किसी और ने नहीं बल्कि खुद विवेकानंद ने यह कहा है। अब यह फैसला राम भक्त करें कि वे विवेकानंद को हिन्दू कहेंगे या नहीं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण ने कहा था कि ईश्वर, अल्ला, गोड सभी एक ही हैं। एक ही अलौकिक शक्ति को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसी तरह जैसे एक्का को हिन्दू जल, मुसलमान पानी और ईसाई वाटर करते हैं। रामकृष्ण ने एक मजिस्द में नमाज अदा की थी और एक चर्च में प्रार्थना की थी। क्या रामकृष्ण और विवेकानंद हिन्दू थे या नहीं? आर.एस.एस.-बीजेपी के नेता क्या कहना चाहेंगे?

### राम और हनुमान की पूजा की होड़ लगा रही हैं सत्ता लोलुप पार्टियां

अचानक राम मंदिर का नारा पुनः उछाला जा रहा है। रामनवमी के अक्सर पर तलवारें लहराते हुए परेड की गईं। जहां तक हम जानते हैं और जैसा रामायण में वर्णन है राम तीर-धनुष लेकर लंका को फतह करने गये थे। अब रामभक्त तलवारें लहरा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण है दशहत फैलाना, हिन्दुओं में धार्मिक उन्माद पैदा करना और उनके अंदर मुस्लिम-विरोधी नफरत को भड़काना। अब तृणमूल कांग्रेस (टीएससी) ने भी आर.एस.एस.-बीजेपी का मुकाबला करने के लिए हनुमान की पूजा शुरू कर दी है। राम और हनुमान में

एक होड़ शुरू हो गई है। उन्हें मैं विभीषण की पूजा शुरू करने की सलाह दूंगा जो भाई के रूप में तो बदनाम है लेकिन उनकी मदद के बिना राम लंका को कभी फतह नहीं कर सकते थे। ऐसी-ऐसी बातें आज देश में हो रही हैं। भारत को मध्ययुगीन अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। यह एक गहरी साजिश है। इस साजिश का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है एक हिन्दू वोट बैंक तैयार करना। यह भी एक खतरनाक बात है। लेकिन इतना ही काफी नहीं रह गया है। जैसाकि हम सभी जानते हैं कि आजकल चुनाव जीतने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपये काले धन की जरूरत होती है। मतदाताओं को काले धन से खरीदा जाता है। अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने काले धन को रोकने की आड में नोटबंदी लागू की थी। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इससे पहले किसी भी चुनाव में काले धन का इतना प्रवाह नहीं हुआ जितना कि हाल ही में सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में देखा गया है। नोटबंदी के बाद उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में काले धन का बोलबाला रहा। अतः असल मकसद है वोट बटोरना, पैसे से वोट खरीदना। चुनाव जीतने के लिए भारी मात्रा में काले धन की जरूरत होती है। कौन मुहैया कराता है यह काला धन? यह काला धन शीर्ष एकाधिकारी पूंजीपतियों, ब्लैकमनी ऑपरेटर्स और बड़े व्यापारियों द्वारा मुहैया कराया जाता है। कभी वे कांग्रेस को विजयी बनाते हैं, कभी बीजेपी को, कभी टीएमसी को और कभी सीपीआई(एम)-नीत फ्रंट को भी। अब चुनाव पैसे के बिना नहीं होता है। यह सिर्फ हमारी पार्टी है जो रोजाना का खर्च चलाने के लिए, आंदोलन संचालित करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए भी जनता से चंदा संग्रह करती है। आपने देखा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस सभा के लिए स्ट्रीट क्लैक्शन के माध्यम से धन संग्रह किया है। लोग हमें कहते हैं, "आप पागल हैं। आप वोट के साथ-साथ पैसा भी मांगते हैं। दूसरे वोट मांगते हैं लेकिन उसके लिए पैसा देते हैं। यही वजह है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं।" हम कहते हैं कि हम इस तरह से चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं। हम अपनी विचारधारा का सौदा नहीं करते हैं। हम विचारधारा-सिद्धांत को छोड़कर अपने जीवन धारण के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अपनी विचारधारा-सिद्धांत को तिलांजली देकर हम वोट नहीं चाहते हैं।

अतः एक तो यह पैसे का खेल है और दूसरे है येन-केन-प्रकारेण किसी भी हद तक गिरकर जीतना। इसीलिए आप पाते हैं इस घृणित वोट बैंक राजनीति की इतनी प्रधानता, जिसमें जातिवाद-साम्प्रदायिकता का कार्ड खेल कर वोट बैंक तैयार किया जाता है और फिर मुस्लिम वोट बैंक, हिन्दू वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक इत्यादि जैसे इन वोट बैंकों का दोहन करते हुए चुनाव में जीत हासिल की जाती है। इस तरह से पूरे भारत को टुकड़ों में बांट दिया गया है। धार्मिक भावनाएं भी इसी उद्देश्य से भड़काई जाती हैं। यह है एक पहलू।

### न तो मुस्लिम दुश्मन हैं हिन्दुओं के और न ही हिन्दू दुश्मन हैं मुसलमानों के - दोनों का दुश्मन है पूंजीवाद

दूसरा पहलू है हिन्दुओं के अंदर मुस्लिम-विरोधी नफरत पैदा करना। 'आप हिन्दू बेरोजगार क्यों हैं? आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि मुसलमान सारे फायदों को हड़प रहे हैं।' इस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, हिन्दू समुदाय के बीच मुस्लिम-विरोधी नफरत अभियान चलाया जाता है। हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा यह समझाया जाता है कि न तो पूंजीवाद, न ही पूंजीपति मालिक दुश्मन हैं, हिन्दुओं के दुश्मन तो ये मुसलमान हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के बीच कट्टरपंथी दलाल भी मुसलमानों की एकता का आह्वान कर रहे हैं ताकि भारत में जिंदा बचा जा सके। वे मुस्लिम आबादी को समझा रहे हैं कि जो पार्टी उन्हें शरण और संरक्षण दे सकती है उसे ही चुने और समर्थन करें। इस तरीके से मुस्लिम क्षत्रप और दलाल

(शेष पृष्ठ 7 पर)



## देशव्यापी मांग दिवस पर...

(पृष्ठ 1 का शेष)

इस्तेमाल आदि की मध्यप्रदेश सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ 13 जून एसयूसीआई(सी) ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। मानसरोवर पार्क से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त, रोहतक को दिया। पार्टी के राज्य सचिव कॉ. सत्यवान ने कहा कि लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों को फसलों का लाभकारी दाम देने का वायदा किया था। इसके शासन के 3 साल पूरे होने पर भी इसने यह वादा नहीं निभाया। मध्यप्रदेश सहित पूरे देश के किसान कर्ज में दबते ही जा रहे हैं। किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। किसान न्यायसंगत मांगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलीबारी करके किसानों की हत्याएं कर दी। दोषी पुलिस अफसरों व राजनेताओं पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

पार्टी के जिला सचिव कॉ. अनूप सिंह और राज्य कमेटी सदस्य कॉ. जयकरण माण्डौठी ने भी प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित किया।

**झज्जर** : मध्यप्रदेश के मंदसौर में किसानों के समर्थन में एसयूसीआई(सी) जिला कमेटी झज्जर द्वारा 14 जून को यहां जोरदार प्रदर्शन किया गया। पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय छोटाराम धर्मशाला में एकत्रित हुए और अम्बेडकर चौक तक गये। वे नारे लगा रहे थे, "6 किसानों की हत्यारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद", "हत्या के दोषी पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं पर मुकदमा दर्ज किया जाये"।

कॉ. जयकरण माण्डौठी और कॉ. करतार सिंह अच्छेज समेत 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन उपायुक्त, झज्जर को दिया। ज्ञापन में पूरे देश के किसानों के कर्ज माफ करने, फसलों के लाभकारी दाम देने, आत्महत्या कर चुके किसानों के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने और हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को स्थाई सरकारी नौकरी देना तथा ग्रामीण गरीबों को पूरा साल काम देने की मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉ. सत्यवान और जिला कमेटी झज्जर के सचिव कॉ. अनूप सिंह मातनहेल ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की कड़ी भर्त्सना की। पहले तो किसानों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का बर्बर हमला किया गया और बाद में उपवास का अस्त्र किसानों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इसे फासीवादी पैतरा करार दिया। पार्टी ने घोषणा की कि किसान आन्दोलन को दबने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सहित जब तक किसानों की कर्ज माफी नहीं की जाती, प्रदेश भर में धरने-प्रदर्शन जारी रहेंगे। नुककड़ सभाएं और श्रद्धांजली सभाएं की जाएंगी।

**भिवानी** : मध्यप्रदेश के मंदसौर में किसानों के चल रहे प्रदर्शन पर हुई पुलिस फायरिंग जिसमें 6 किसान मारे गए और कई गम्भीर रूप से घायल हुए, इस जघन्य गोलीकाण्ड के खिलाफ एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) जिला कमेटी भिवानी की तरफ से 14 जून को यहां स्थानीय नेहरू पार्क में श्रद्धांजली सभा की गई। सभा की अध्यक्षता पार्टी के भिवानी लोकल कमेटी सचिव कॉ. राजकुमार ने की। इसके बाद वहां से हांसी गेट तक प्रदर्शन किया गया। पार्टी के एक प्रतिनिधिमण्डल ने उपायुक्त, भिवानी की मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के भिवानी जिला सचिव कॉ. रामफल ने कहा कि यह आन्दोलनकारी किसानों पर घोर जुल्म, दमन-उत्पीड़न और घोर बर्बरता पूर्ण कार्य है जो काफी निन्दनीय है। इस अमानवीय घटना ने भाजपा सरकार का किसान-विरोधी, तानाशाहीपूर्ण और अलोकतांत्रिक चेहरा बेनकाब कर दिया है।

पार्टी के जिला कमेटी सदस्य कॉ. जिले सिंह ने कहा कि खेती में घाटे के कारण मध्यप्रदेश में हजारों किसान कर्ज में दबकर आत्महत्या कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने कर्ज माफ करने का वादा करने पर भी उनकी कोई सुध नहीं ली। लेकिन किसानों द्वारा अपनी जायज आवाज उठाने पर किसान आन्दोलन का दमन किया गया और पुलिस फायरिंग करके किसानों को मौत के घाट



उतारने की निर्मम कार्रवाई की गई। एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) नेताओं ने किसानों की मौत पर गहरा रोष प्रकट किया।

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव कॉ. रोहतास सिंह सैनी ने मध्यप्रदेश सरकार की दमनकारी कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि म.प्र. सरकार ने पहले तो किसानों की आवाज दबाने के लिए किसानों को गोलियों से भून डाला और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खिलाफ उपवास के अस्त्र का इस्तेमाल किया। इन फासीवादी हथकण्डों को जनता सब समझती है। मृतक किसानों के परिवारों के प्रति हमदर्दी व शोक संवेदना जताने गए राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किये जाने का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया।

प्रदर्शन में सुखबीर, राजकुमार, धर्मवीर सिंह, राजकुमार बासिया, संदीप मेहरा, मनोहर लाल, मनीराम, सूबे, विशाल, सत्यवान, फूल सिंह, ममता, जयवीर, प्रेम, शारदा आदि अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए।

**तोशाम, भिवानी में पुतला दहन** : मंदसौर, मध्यप्रदेश में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोली चलाये जाने के विरोध में ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने आज दिनांक 8 जून 2017 को यहां झगडू होटल चौक पर भाजपा की मध्यप्रदेश सरकार का पुतला फूँका। बर्बर गोलीकाण्ड की कड़ी निंदा करते हुए संगठन के जिला सचिव कॉ. रोहतास ने कहा कि भाजपा सरकार घोर किसान-विरोधी है। किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान कॉ. जिले सिंह ने किसान की जायज मांगों मानने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा अंजाम दिये गए किसानों के इस बर्बर हत्याकाण्ड के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सभी मेहनतकशों और जनतांत्रिक सोच के लोगों, खासकर किसान-मजदूरों को आगे आने का आह्वान किया। सुखबीर, दीप कुमार, जयवीर, फूल सिंह, नरसिंह, बीर सिंह, राजकुमार, राजकुमार, ओम आदि भी इस मौके पर मौजूद थे।

इसके बाद किसान खेत-मजदूर संगठन के एक प्रतिनिधिमण्डल की ओर से एसडीएम, तोशाम की मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि इस घटना की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, हर मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपये और घायल को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाये, गोलीकाण्ड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त पुलिस अधिकारियों व राजनैतिक नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया जाये और उदाहरणमूलक सजा दी जाये, किसानों को उनकी सभी फसल के लाभकारी दाम दिये जायें और किसानों के कर्ज खत्म किये जायें।

**छ.ग.**

**दुर्ग** : मंदसौर(म.प्र.) में आन्दोलनकारी किसानों पर पुलिस फायरिंग के विरोध में एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) जिला कमेटी दुर्ग की तरफ से 8 जून को यहां जोरदार प्रदर्शन किया गया। किसानों की जायज मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया।

**बिहार**

**पटना** : मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों पर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा फायरिंग कर 6 किसानों की जान लेने तथा अनेकों को घायल करने के खिलाफ 14 जून को राष्ट्रव्यापी मांग दिवस के मौके पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमेटी के तत्वावधान में गांधी

(पृष्ठ 6 का शेष)

**तोशाम**

## देशव्यापी मांग दिवस पर...

(पृष्ठ 5 का शेष)

मैदान स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर शहीद वेदी का निर्माण कर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गयी।

तदुपरांत वहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) बिहार राज्य सचिव कां. अरुण कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा व विधान सभा चुनावों में किसानों को फसलों के लाभकारी दाम देने का वायदा किया था। तीन साल पूरे होने पर भी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नहीं निभाया। मध्य प्रदेश सहित देशभर के किसान कर्ज में दबते ही जा रहे हैं और उनकी आत्महत्याओं की तादाद निरंतर बढ़ रही है। पार्टी की पटना जिला सचिव साधना मिश्रा ने कहा कि देशभर में सरकारों की किसान-विरोधी नीतियों के चलते किसान आज बदहाली में जी रहे हैं। खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक आदि से सब्सिडी खत्म कर लगातार इनके दाम बढ़ाये जा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं।

अपने संबोधन में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कमिटी सदस्य मणिकांत पाठक ने कहा कि सरकारें बड़े-बड़े कारपोरेट घरानों को खेती में मुनाफा कमाने की खुली छूट दे रही हैं। चन्द कारपोरेट घरानों पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है, जिसे एनपीए के तहत माफ कर दिया गया है। वहीं देशभर के करोड़ों किसानों पर कुल 1 लाख करोड़ रुपये से भी कम का कर्जा है, जिसे सरकारों द्वारा माफ नहीं किया जा रहा है। किसानों पर मुकदमे दायर किये जाते हैं। बैंकों द्वारा उनकी जमीनों की निलामी कर दी जाती है। यह सब सरकारों की पूंजीपतिपरस्त और किसान-विरोधी नीतियों की वजह से हो रहा है। सभा को एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पटना जिला कमिटी सदस्य कां. सूर्यकर जितेन्द्र, बैद्यनाथ शर्मा, राजेन्द्र राय आदि ने भी संबोधित किया।

राजधानी पटना के अलावा मुजफ्फरपुर जिले में मुजफ्फरपुर शहर, कांटी, महंथ मनियारी, सैरैया, साहेबगंज, मीनापुर; मुंगेर जिले में मुंगेर शहर, हवेली खडगपुर; वैशाली जिले में महुआ तथा बांका जिले में बेलहर में शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध कार्यक्रम किये गये।

### मध्य प्रदेश

**गुना :** मध्यप्रदेश के मंदसौर में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए किसानों की याद में एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की तरफ से 14 जून को यहां हनुमान चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा की गई। सभा को जाने-माने बुद्धिजीवी प्रो. श्याम मोहन और ट्रेड यूनियन नेता नरेन्द्र सिंह भदोरिया आदि ने संबोधित किया और पुलिस फायरिंग करवा कर किसान आन्दोलन को दबाने के बीजेपी सरकार के प्रयास की कड़ी निन्दा की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) के नेता कां. लोकेश शर्मा ने सरकार की किसान-विरोधी व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आन्दोलन गठित करने के लिए किसानों का आह्वान किया।

सभा का संचालन कां. प्रदीप आरबी ने किया।

**देवास :** मध्य प्रदेश के मंदसौर में आन्दोलनकारी किसानों को गोली मार कर मौत के घाट उतारने वाली म.प्र. सरकार का एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की तरफ से 7 जून को यहां भोपाल चौराहा पर पुतला दहन किया गया। विरोध प्रदर्शनकारियों को पार्टी के जिला प्रभारी कां. हिमांशु श्रीवास्तव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों, माल्या जैसे डिफाल्टरों के बैंक कर्ज बटूटे खाते में डाल रही है, उनके टैक्स माफ कर रही है वहीं भूखे मरते किसानों की जायज मांगों को लेकर हो रहे आन्दोलन को दबाने के लिए लाठी-गालियां चला रही है। मंदसौर में किसानों की मौत पर अफसोस जताने की बजाय गृहमंत्री बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। मनघड़त कहानी बना कर पुलिस को क्लीन चिट देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। केवल मंदसौर में ही नहीं, एक समय पर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस ने किसानों पर बल प्रयोग किया जो साफ दर्शाता है कि किसानों को मौत के घाट उतारने के फरमान सरकारी हैं। 7 जून को सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में एसयूसीआई(सी) सहित तमाम वामपंथी दलों ने संयुक्त विरोध दिवस मनाया। इसी क्रम में देवास में भी प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन सौपा गया।

प्रदर्शन को ऑल इण्डिया डीएसओ के जिला समिति सदस्य विनोद प्रजापति, मनोहर और महिला सांस्कृतिक संगठन की जिला प्रभारी वाणी जाधव ने भी संबोधित किया। मध्यप्रदेश सरकार के मानक पुतले को विनोद प्रजापति ने आग के हवाले किया। सुनील सिंह राजपूत ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते किसानों की मांगों नहीं मानी तो आन्दोलन और तेज होगा। मंदसौर घटना पर म.प्र. के मुख्यमंत्री के इस्तिफे की भी मांग की गई।

### उ.प्र.

**इलाहाबाद ( उ.प्र. ) :** मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर गोली चलाकर पुलिस द्वारा की गई 6 किसानों की हत्या के खिलाफ 9 जून को एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की इलाहाबाद जिला इकाई की पहल पर चार वामपंथी पार्टियों का संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना जिलाधिकारी कार्यालय इलाहाबाद में किया गया। धरने के बाद पांच सूत्रीय मांगों का राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी इलाहाबाद के माध्यम से सौपा गया।

सभा को संबोधित करते हुए एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की इलाहाबाद जिला इकाई के सदस्य कॉमरेड के. सिंह ने कहा कि केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार किसानों को लागत का डेढ़ गुना फायदा पहुंचाने तथा कर्ज माफ करने के वायदे के साथ सत्ता में आयी थी किन्तु सरकार में आते ही किसानों से धोखा करते हुए अपने वायदे से मुकर गयी। सरकार पूंजीपतियों की सेवा में इस कदर व्यस्त है कि पूंजीपतियों का एक साल में 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज माफ कर दिया तथा आते ही कारपोरेट टैक्स में 5 प्रतिशत की छूट दे दी, वहीं किसानों की जायज मांगों को सुनने तक का सरकार के पास समय नहीं है उल्टे देशभर में आन्दोलनरत किसानों के साथ संवेदनहीनता के



पटना : प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए कां. अरुण कुमार सिंह



मुजफ्फरपुर



बेलहार, बांका



दुर्ग



गुना

साथ पुलिस के माध्यम से आन्दोलनों को कुचला जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश में मारे गये व घायल हुए किसानों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए 40 प्र0 सराकार की ओर से जारी घटिया और झूठी बयानबाजी की भर्त्सना की। (शेष पृष्ठ 8 पर)



**कॉ. प्रभास घोष का भाषण**

(पृष्ठ 4 का शेष)



कोलकाता, शहीद मीनार मैदान में 24 अप्रैल की सभा का एक दृश्य

भी मुस्लिम वोटों को नियंत्रित करते हैं, ध्रुवीकृत वोटों को इस या उस पार्टी के समर्थन में जुटाते हैं और इस प्रकार व्यक्तिगत लाभ बटोरते हैं। इस तरह से दोनों तरफ के निहित स्वार्थ वाले तत्व लोगों की एकता को तोड़ रहे हैं। यह एक पहलू है। इसी के साथ-साथ लोगों को धर्मान्धता के जाल में फंसाने और उनकी चिंतन प्रक्रिया को कुंद कर देने, उनके वैज्ञानिक और तार्किक मनन के साथ-साथ उनकी तर्क करने की शक्ति को तबाह करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। यह एक और साजिश है, फासीवादी षडयंत्र है। कॉमरेड शिवदास घोष ने बहुत पहले बताया था कि दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी-इटली-जापान फासिस्टों को दी गई शिकस्त के बावजूद पूंजीवाद की इस घोर प्रतिक्रियावादी अवस्था में फासीवाद विभिन्न रूपों में केवल विकसित पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में ही नहीं बल्कि विकासशील पूंजीवादी देशों में भी एक आम विशेषता बन चुका है। उन्होंने फासीवाद के तीन चारित्रिक लक्षणों को दिखाया था। (1) एकाधिकारी पूंजी के रूप में पूंजी का संकेन्द्रीकरण। बहु पूंजी के दिनों के दौरान असंख्य छोटी-छोटी पूंजियां होती थी। उस समय बहु-पार्टी डेमोक्रेसी थी। अब ज्यादातर छोटी और मझौली पूंजियों को निगलने के जरिये चंद इजारेदार यानी एकाधिकारी पूंजीपतियों के हाथ में पूंजी केन्द्रित हो गई है। इस पृष्ठभूमि में डेमोक्रेसी पहले की तरह उदार और व्यापक नहीं रह गई है। अर्थव्यवस्था केन्द्रीकृत है। (2) पूंजीवादी राजसत्ता के हाथों में राजनैतिक शक्ति का अधिकाधिक केन्द्रीकरण। (3) आध्यात्मवाद और विज्ञान के तकनीकी पहलुओं के बीच विचित्र सम्मिश्रण के माध्यम से सांस्कृतिक रेजिमैंटेशन। चिंतन के क्षेत्र में विज्ञान का कोई स्थान नहीं रहेगा। आध्यात्मवादी चिंतन, धार्मिक विचारों, भगवान की अवधारणा, भाग्यवाद का सिद्धांत और कर्मों का फल जिनके खिलाफ अपने उदयकाल के दौरान 18वीं और 19वीं शताब्दियों में पूंजीवाद लड़ा था, इन तमाम को खुद उसके द्वारा ही वापस लाया जा रहा है। वही पूंजीपति वर्ग अब अपनी सड़ी-गली मरणासन प्रतिक्रियावादी अवस्था में इस विचित्र सिद्धांत के पुनर्स्थापन को बढ़ावा दे रहा है कि वर्तमान जीवन में हम पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं। आज क्यों कुछ लोग अति धनाढ्य हैं? 'चूंकि इन्होंने अपने पिछले जन्म में तमाम पवित्र काम किये थे, इसलिए इन्होंने इतनी भारी दौलत कमाई है और अपने वर्तमान जीवन में मजदूरों और आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। पिछले जन्म में किये गए उनके पुण्य का फल है यह। और तुम लोग, विशाल सर्वसाधारण दुःख भुगत रहे हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में पाप किये थे'—ऐसे ही विचारों को शासक हलके आज फैला रहे हैं। 'तर्क मत करो, सवाल मत उठाओ, इन-दुःख-तकलीफों से तुम्हें कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है क्योंकि ये तुम्हारे पिछले जन्म में किये गये गलत कर्मों का फल है। इन तमाम विचारों को ब्रह्म वाक्य मान करके स्वीकार कर लो। राज्य के नेताओं का अंधतापूर्वक अनुसरण करते रहो और शासक पार्टी के बारे में कोई सवाल मत उठाओ। उनके खिलाफ तर्क करने का प्रयास मत करो। क्योंकि

आज जो कष्ट तुम उठा रहे हो यह तो विधि का विधान है, परमात्मा द्वारा पूर्व निर्धारित है।' इस तरह की कुंद अंधी मानसिकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूंजीवाद को आज इसकी जरूरत है। विज्ञान की जरूरत सिर्फ तकनीकी विकास के लिए है। कल दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह मांग करते हुए 600 देशों में रैलियां निकाली कि विज्ञान को राष्ट्रों की राजनीति और नेताओं यानी पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करो। यह खबर आज के अखबारों में छपी है। पूंजीवाद विज्ञान के विकास और प्रगति को रोक रहा है। पूंजीवाद विज्ञान को सिर्फ हथियार और मशीनों बनाने के लिए चाहता है। यह वैज्ञानिक विचारों, वैज्ञानिक मनन, जिज्ञासु मन, वैज्ञानिक तर्क पर आधारित चर्चा-बहसों, कार्य-कारण संबंध के बारे में जानने की जिज्ञासा, वैज्ञानिक नजरिये की कसौटी पर इतिहास का विश्लेषण आदि आदि को पनपने और विकसित होने की इजाजत नहीं देता है। सिर्फ पूंजीवाद का क्रूर निर्मम शोषण बेरोकटोक जारी रहना चाहिए। यही आज वे चाहते हैं।

शासक पूंजीपति वर्ग फासीवादी सोच विकसित करने के लिए धर्मान्धता को उकसा रहा है। यह कह कर कि 'मुसलमान हिन्दुओं के दुश्मन हैं', 'हिन्दू मुसलमानों के दुश्मन हैं', 'तथाकथित नीची जाति के लोग ऊंची जाति के और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के दुश्मन हैं'; 'दूसरे प्रांतों से महाराष्ट्र आने वाले लोग महाराष्ट्रीयन के दुश्मन हैं'; 'आसाम या उड़ीसा में दूसरे प्रांतों के लोगों का प्रवेश इन प्रांतों के मूल निवासियों के हितों के खिलाफ है'; 'एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जायेगी'; 'एक प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत के खिलाफ खड़े हो जाने दो'—इस तरह वे लोगों की एकता को तोड़ने और वोट बैंक तैयार करने के एकमात्र उद्देश्य से देश को बांट रहे हैं।

**हिन्दूवाद के प्रचारकों ने कभी नहीं उठाई गोवध के निषेध की मांग**

इन तमाम के साथ गोवध पर रोक लगाने का नारा और जोड़ दिया गया है। हिन्दूवाद के प्रचारकों ने कभी ऐसा नारा नहीं उठाया। आज इस किस्म का हौवा उठा कर हिन्दू साम्प्रदायिकता को भड़काने का मनहूस प्रयास हो रहा है। इस मुद्दे पर वेद, रामायण और महाभारत से कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुनाता हूं। देवराज इन्द्र के सामने प्रार्थना है, "कृपया मेरे लिए 15 से 20 बैल पकाये जाएं ताकि मैं अपने पेट के दोनों भागों को भर सकूँ और मोटा हो जाऊँ।" (ऋग्वेद संहिता, 10वां खंड, 86वां सुक्त, 14वां मंत्र) इन्द्र के सामने दूसरी प्रार्थना है, "जैसे बूचड़ खानों में गाय कत्ल की जा रही है, उसी तरह हमारे दुश्मन राक्षसों का वध भी आपके शस्त्र द्वारा किया जाना चाहिए और धरती पर शांति कायम करनी चाहिए।" (ऋग्वेद संहिता, 10वां खंड, 86वां सुक्त, 14वां मंत्र) यह दर्शाता है कि उस समय साधु लोग गोमांस खाते थे। वैदिक साहित्य के सतपथ ब्राह्मण में ऋषि जगदंबिका के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि यदि गोमांस नरम है तो खाया जा सकता है। (तीसरा खंड, प्रथम अब्दा, दूसरा पैराग्राफ, सतपथ

ब्राह्मण का 21वां मंत्र) यह दर्शाता है कि उस समय भोजन के रूप में गो मांस परोसा जाता था। यदि मैं रामायण से उदाहरण पेश करूँ तो हो सकता है रामभक्त मुझ पर शारीरिक हमला बोलने को उद्यत हो जायें। कृपया सुनिये वहां क्या लिखा है, "जब राम सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के लिए वनों की तरफ जाने के रास्ते में ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर पहुंचे तो ऋषि ने उनकी आवभगत गोमांस और फलों से की।" (वाल्मीकि रामायण, दूसरा खण्ड, 54वां सर्ग) साफ तौर से राम के सामने गोमांस परोसा गया जब वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में गये। दूसरे शब्दों में, प्राचीन भारत में गोमांस खाने का रिवाज था। मेहमानों की आवभगत गोमांस से की जाती थी। बुद्ध धर्म और जैन धर्म आने के बाद पशु बलि बंद हो गयी थी। बाद में उच्च जाति के हिन्दुओं द्वारा भी गोमांस खाना बंद कर दिया गया था। हो सकता है कोई आर्थिक कारण रहा हो। गोवध हो सकता है इस वजह से बंद हो गया हो कि कृषि के लिए खेत जोतने या अन्य उपयोगी जरूरतों के लिए गायों की जरूरत होती थी। इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। विवेकानंद ने भी कभी गोवध बंद करने की बात नहीं कही। गुरु-शिष्य संवाद में यह वर्णन है कि जब विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तभी 'गो रक्षा समिति' के सदस्य उनसे चंदा मांगने के लिए आये। विवेकानंद ने उनसे पूछा, "आप लोगों का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि वे कसाइयों से गोमाता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। विवेकानंद ने उनसे कहा, "आपके वित्त पोषण का स्रोत क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि वे चंदे के जरिये फण्ड जुटाते हैं। तब विवेकानंद ने कहा, "मध्य भारत भयंकर अकाल की चपेट में है। भारत सरकार ने 9 लाख लोगों की लिस्ट जारी की है जो भुखमरी से मर गये। आपकी समिति ने वहां के प्रभावित लोगों के लिए मदद करने के क्या कदम उठाये हैं?" उन्होंने उत्तर दिया कि वे अकाल पीड़ितों की कोई मदद नहीं करते हैं। वे सिर्फ गोमाता की रक्षा के लिए मदद कर रहे हैं। विवेकानंद ने कहा, "आप अपने देशवासियों की मदद नहीं कर रहे जो मर रहे हैं बल्कि गोमाता की रक्षा के लिए चंदा संग्रह कर रहे हैं?" उन्होंने उत्तर दिया लोग मर रहे हैं क्योंकि इस अकाल की वजह अतीत में किये गये उनके पाप कर्म हैं। जैसा उन्होंने बोया वैसा काट रहे हैं। उनका उत्तर सुनकर विवेकानंद बहुत क्रोधित हो गये। लेकिन अपने गुस्से को दबाकर उन्होंने कहा, "मुझे उन समितियों या संगठनों से कोई सहानुभूति नहीं है जो इन्सानों की दुःख-तकलीफों से हमदर्दी नहीं रखते, जो अपने भूखे मर रहे भाइयों के लिए कुछ खाना नहीं जुटाते और उनका जीवन नहीं बचाते बल्कि इसकी बजाय पक्षियों और पशुओं के लिए ढेरों अनाज बांट देते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि ऐसे काम करके समाज की कोई भलाई की जा रही है। यदि कोई तर्क देता है कि अपने पिछले पापों की वजह से लोग मर रहे हैं तब इस दुनिया में कुछ भी करने का प्रयास एक निरर्थक काम बन कर रह जाएगा।" विवेकानंद ने आगे कहा, "फिर तो आपके काम के बारे में भी कहा जा सकता है कि गोमाता को उनके अतीत के पापों की वजह से बूचड़ खाने में ले जाया और मारा जा रहा है। हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है।" फिर स्वामी जी (विवेकानंद) अपने शिष्यों की तरफ मुड़े और कहा कि "यह इस बात का जीता-जागता प्रणाम है कि किस तरह देश रसातल में जा रहा है। क्या आप हिन्दू देख पाते हैं कि किस निम्न स्तर पर तुम्हारा गो-रक्षा अभियान पहुंच गया है?" इसलिए आज के गो रक्षण की बात का धर्म से कुछ लेना-देना नहीं है।

आरएसएस-बीजेपी ने देश में ऐसा माहौल तैयार कर दिया है मानो आज एकमात्र काम रह गया है राम मंदिर स्थापित करना और गोवध को बंद करना। मान लेते हैं दोनों ही 'कार्य' धर्म के नाम पर पूरे कर दिये जाते हैं। फिर क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं रहेगी? फिर क्या कारखाने बंद नहीं होंगे, छंटनी नहीं होगी, महंगाई नहीं बढ़ेगी, टैक्स नहीं बढ़ेंगे, बस-रेल किरायों में बढ़ोतरी नहीं होगी? क्या जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा? बीजेपी-आरएसएस इन सवालों का जबाब देना नहीं चाहते हैं। वे तो राम मंदिर और गोवध बंद करने का नारा इन मूल सवालों को दबाने के लिए उछाल रहे हैं। ये एक भयंकर षडयंत्र है। (शेष अगले अंक में)

## सीपीआई(एम) की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कायराना हमले की एसयूसीआई(सी) ने की कड़ी निन्दा

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने 8 जून, 2017 को जारी एक बयान में कहा :

दिल्ली में 7 जून, 2017 को सीपीआई(एम) के मुख्यालय पर बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई(एम) के महासचिव सीताराम येचुरी पर कथित तौर पर आरएसएस से जुड़े दो शरारती तत्वों द्वारा किये गए बेहद कायराना हमले की हम कड़ी निन्दा करते हैं। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि फासीवादी रास्ते पर चलने वाली प्रतिक्रियावादी ताकत की तरह ही आरएसएस अपना वैचारिक-राजनैतिक वर्चस्व थोपने के लिए अब बाहुबल का प्रयोग करके विपक्ष की आवाज का गला घोटने पर उतारू है।

सभी समझदार और जनवादी ख्यालात वाले लोगों को इस घिनौने हमले की भर्त्सना करनी चाहिए और एकताबद्ध संगठित सचेत आन्दोलन गठित करने के लिए लामबंद हो जाना चाहिए ताकि फासीवादी ताकतों को परास्त किया जा सके।

## मंसौर (म.प्र.) में पुलिस फायरिंग ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

शर्तों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा कर रही हैं ताकि वे हितलाभ गरीब किसानों के लिए मृग मरीचिका बने रहें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खेती का कर्ज माफ करने की गई घोषणा वैसा ही छलावा है क्योंकि बदहाली से ग्रस्त कंगाल कर दिये गए किसान बताया गई शर्तों को पूरा नहीं कर पायेंगे। अब जब किसानों को अपनी मांगों के लिए मजबूर कर दिया गया है, तब सरकार गोलियों से जवाब देती है और केन्द्रीय गृह मंत्री जैसे निरंकुश नेता म.प्र. सरकार से कहते हैं कि 'अव्यवस्था फैलाने वालों' से सख्ती से निपटे। जहां सरकार पिछले वित्त वर्ष में दरियादिली के साथ बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों और धन कुबेरों के 9 लाख करोड़ रुपये के टैक्स माफ कर सकती और टैक्सों में छूट दे सकती है, वहां इसके प्रवक्ता अब अर्थव्यवस्था घाटे में होने के बहाने कृषि कर्ज माफ करने का बेशर्मी से विरोध कर रहे हैं। देशवासियों से वादा किये गये अच्छे दिनों का यह हाल है।

मध्य प्रदेश में भयावह पुलिस फायरिंग काण्ड के खिलाफ 8 जून को देशव्यापी विरोध दिवस पालन करने का हम आह्वान करते हैं। पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने और इस जघन्य अपराध के दोषी पुलिस अफसरों और राजनेताओं को सख्त सजा देने की मांग करते हुए हम संघर्षरत किसानों से अपील करते हैं कि वे प्रतिक्रियावादी और समझौतापरस्त ताकतों की मीठी-मीठी लुभावनी बातों या लड़ाकूपन के दिखावटी तेवरों के बहकावे में न आये बल्कि इसकी बजाय अपने जायज आन्दोलन को इसकी तर्कसंगत मंजिल तक ले जाने के लिए सही क्रान्तिकारी नेतृत्व में एकताबद्ध संगठित सचेत दीर्घकालिक जोरदार आन्दोलन गठित करें।

## संघर्ष की राह पर आंगनवाड़ी वर्कर



सोनीपत : लगातार धरना देते हुए आंगनवाड़ी वर्कर

सोनीपत (हरियाणा), 14 जून : चार बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्करों की बहाल करने व 1482 वर्करों को दिये गये कारण बताओ नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर एआईयूटीयूसी व हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच (जेपीए) से सम्बन्धित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन द्वारा अग्रसैन चौक नजदीक कविता जैन-राजीव जैन निवास सैक्टर-15 सोनीपत पर शुरू किया गया धरना बुधवार को आठवें दिन भी जारी रहा। धरने का नेतृत्व सरोज देवी ने किया जबकि संचालन ममता ने किया। धरने में हिसार और झज्जर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने भाग लिया।

हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के प्रदेशाध्यक्ष आर के नागर और एआईयूटीयूसी के नेता कॉ. रामकरण ने धरनास्थल पर पहुंच कर महिलाओं की मांगों का समर्थन

किया और बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्करों की बहाली की मांग की। यूनियन की प्रदेश महासचिव पुष्पा दलाल, बिमला नैन, रोशनी चौधरी, गीता, सुनीता, निर्मला व अंजना ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने मांग की कि बर्खास्त आंगनवाड़ी वर्करों को शीघ्र बहाल किया जाए और गर्मियों की छुटियां लागू करने के आदेश दिये जायें।

एआईयूटीयूसी के जिला व राज्य नेता कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी, कॉ. इन्द्र सिंह, कॉ. धर्मसिंह, कॉ. नरेन्द्र दहिया ने भी धरने का समर्थन किया अपने विचार रखे। उन्होंने भविष्य में भी आंगनवाड़ी वर्करों के आन्दोलन का भरपूर सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विभागीय मंत्री व मुख्यमंत्री से आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगें शीघ्र पूरी करने की मांग की।

## देशव्यापी मांग दिवस पर...

(पृष्ठ 6 का शेष)

सभा को एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) की ओर कॉ. घनश्याम मोर्य ने भी संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता सी.पी.आई.के कॉम. नसीम अंसारी ने की। सभा का संचालन एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) की इलाहाबाद जिला इकाई के सदस्य कॉमरेड राजवेन्द्र सिंह ने किया। धरने में किसान संघर्ष समिति बारा के संयोजक इन्द्रो सिंह, डॉ. एम.एल. यादव, अधिवक्ता अभय सिंह, पवन श्रीवास्तव, शिवकुमार, राजकुमार, सिद्धार्थ, अरमान, रत्नेश, आरिफ, ए.आई.डी. एस.ओ. के कॉम. भीम सिंह, राकेश सहित दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता-नेता शामिल रहे।

अमरोहा : मध्य प्रदेश के मंसौर में जायज मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे किसानों की पुलिस फायरिंग में हुई हत्याओं के खिलाफ 7 जून को ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन की जिला अमरोहा (उ.प्र.) इकाई ने कॉ. शील कुमार की अगुवाई में जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया तथा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी बैनर, पट्टियां लिए थे तथा नारे लगाते हुए डी.एम. कार्यालय पहुँचे। प्रदर्शनकारियों में देवराज, बलबीर, धर्मपाल, गम्भीर सिंह, इन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह एडवोकेट, जसवीर सिंह, महेन्द्र सिंह, कमलेश चहल, दिग्गज सिंह शामिल थे। कलैक्ट्रेट पहुंचकर पहले से चल रहे 'भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैट धड़े' के साथ मंच साझा किया। इसमें एसयूसीआई (सी) जिला सचिव कॉ. शील कुमार, राजेन्द्र व कमलेश चहल ने बात रखी।



హైదరాబాద్